

## दिल्ली में वधायी शक्तियों का टकराव

### प्रलिमिंस के लिये:

भारत के संविधान में 69वाँ संशोधन।

### मेन्स के लिये:

नई दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन।

## चर्चा में क्यों?

दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के कारण नई दिल्ली के क्षेत्रीय प्रशासन के लिये नरिवाचति सरकार और उपराज्यपाल (LG-केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) के बीच शक्तियों को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है।

- दोनों के बीच कई अवसरों पर विवाद हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार नरिोधक ब्यूरो, सविलि सेवा और बजिली बोर्ड जैसी एजेंसियों पर नियंत्रण शामिल है।
- इसके अलावा [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991](#) में हुआ 2021 का संशोधन बताता है कि संघर्ष की संभावना खत्म नहीं हुई है।

## Centre vs Delhi govt again

### WHAT THE Act PROPOSES

- The term "Government" in any law by the legislative assembly will mean "Lieutenant Governor"
- The assembly shall not make rules or committees to consider day-to-day administration or conduct inquiries
- Rule or committee made before the new amendment comes into force "shall be void"
- Before taking any executive action, opinion of the L-G shall be obtained by a general or special order
- L-G shall have power to reserve for consideration any Act, and any of the matters outside the purview of the powers conferred on the legislative assembly

### DELHI GOVT'S RESERVATIONS

- Article 239AA says legislature can make laws on any matters on state and concurrent list except for issues relating to public order, police and land.
- SC's Constitution bench in 2018 recognised assembly's right, and said Union has exclusive powers only in the above 3 issues.
- SC said L-G should work with aid and advice of council of ministers
- SC order clarified that L-G has not been entrusted with any independent decision-making power
- While any matter of dispute can be sent to President, the SC said it does not mean every matter should be

## नई दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल:

- संविधान की अनुसूची 1 के तहत दिल्ली को केंद्र शासति प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त है जबकि संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239AA के तहत 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' का नाम दिया गया है।
- 69वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 239AA को सम्मलित किया गया, जिसने केंद्रशासति प्रदेश दिल्ली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासति करने की घोषणा की, जो नरिवाचति विधानसभा की सहायता एवं सलाह पर काम करता है।
  - हालाँकि 'सहायता और सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधित है, जिन पर नरिवाचति विधानसभा के पास राज्य व समवर्ती सूचियों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि के अपवाद के साथ अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके अलावा अनुच्छेद 239AA यह भी कहता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है या वह राष्ट्रपति द्वारा किसी संदर्भ में लिये गए नरिणय को लागू करने के लिये बाध्य होता है।

- साथ ही अनुच्छेद 239AA के अनुसार, उपराज्यपाल के पास मंत्रपरिषद के नरिणय को राष्ट्रपति के वचिारार्थ आरक्षति करने की वशिष शक्तिर्णि हैं ।
- इस प्रकार उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच इस दोहरे नरिर्णय से सत्ता-संघर्ष की स्थति उत्पन्न होती है ।

## इस मामले में न्यायपालिका की राय:

- दलिली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रशासति प्रदेश के रूप में दलिली की स्थतिको देखते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में नरिणय कथिा गया ।
- हालौंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor-LG) की तुलना में दलिली की चुनी हुई सरकार की शक्तिर्णि से संबंधति कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर फैसला करने हेतु मामले को एक संवधान पीठ को संदर्भति कर दथिा गया ।
- संवैधानकि पीठ को संदर्भति मामले को एनसीटी बनाम यूओआई मामला, 2018 (NCT vs UOI case, 2018) के रूप में जाना जाता है । पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने NCT के प्रशासन में एक नया न्यायशास्त्रीय अध्याय के मार्ग को प्रशस्त कथिा ।
  - उद्देश्यपूर्ण नरिमाण: न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण नरिमाण के नयिम का हवाला देते हुए कहा कि संवधान (69वाँ संशोधन) अधनियिम के पीछे उद्देश्य अनुच्छेद 239AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करना है ।
    - अर्थात् अनुच्छेद 239AA में संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत शामिल हैं, जसिसे अन्य केंद्रशासति प्रदेशों से भिन्न स्थति प्रदान करने की संसदीय मंशा का पता चलता है ।
  - उपराज्यपाल द्वारा सहायता और सलाह पर कार्रवाई करना: न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल मंत्रपरिषद की "सहायता और सलाह" के अधीन कार्य करता है, यह देखते हुए कि दलिली वधानसभा के पास राज्य सूची में शामिल तीन वशिषों को छोड़कर समवर्ती सूची में शामिल सभी वशिषों पर कानून बनाने की शक्ति है ।
    - उपराज्यपाल को मंत्रपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना चाहथि, सवािय इसके कविह कसिी मामले को अंतमि नरिणय के लथि राष्ट्रपतिको संदर्भति करे ।
  - हर मामले में लागू नही: कसिी भी मामले को राष्ट्रपतिको संदर्भति करने के लथि उपराज्यपाल की शक्ति, जसि पर उपराज्यपाल और मंत्रपरिषद के बीच मतभेद है, के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कथिा कि "कसिी भी मामले" का अर्थ "हर मामले" से नही लगाया जा सकता है, " और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण परिस्थतिर्णि में ही उत्पन्न होगा ।
  - सहायक के रूप में उपराज्यपाल: उपराज्यपाल स्वयं को नरिवाचति मंत्रपरिषद के वशिधी के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा ।
  - नई दलिली को राज्य का दर्जा नही दथिा जा सकता: साथ ही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली को संवैधानकि योजना के तहत राज्य का दर्जा नही दथिा जा सकता है ।

## आगे की राह

- संवैधानकि वशिवास के माध्यम से कार्य करना: शीर्ष अदालत ने सही नषिकर्ष नकाला था कि संवधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली सरकार अधनियिम, 1991 में नरिर्णयति योजना एक सहयोगी संरचना की परकिल्पना करती है जसि केवल संवैधानकि वशिवास के माध्यम से ही साकार कथिा जा सकता है ।
- सब्सिडियरी का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity) सुनश्चिति करना: सब्सिडियरी (राजकोषीय संघवाद का संस्थापक) सिद्धांत आवश्यक रूप से उपराष्ट्रीय सरकारों को सशक्त बनाता है ।
  - इसलथि केंद्र सरकार को शहरी सरकारों को अधिक-से-अधिक शक्तिर्णि आवंटति करने की दशिा में आगे बढ़ना चाहथि ।
  - इस संदर्भ में भारत को जकार्ता और सथिोल से लेकर लंदन व पेरसि जैसे महानगरों का अनुसरण करना चाहथि जहाँ मज़बूत उप-राष्ट्रीय सरकारें कार्यरत हैं ।

## स्रोत: द हट्टि